



सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

प्रयागराज, सोमवार, 28 फरवरी, 2023 ई०
(फाल्गुन 9, 1944 शक संवत्)

उत्तर प्रदेश, शासन

ऊर्जा विभाग

[ऊर्जा (नि०नि०) प्रकोष्ठ]

उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग, लखनऊ

संख्या उ०प्र०वि०नि०आ०/सचिव/विनियमावली/746

लखनऊ, दिनांक : 28 फरवरी, 2023 ई०

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग, लखनऊ

उ०प्र० विद्युत नियामक आयोग (टैरिफ निर्धारण की प्रक्रिया) विनियमावली, 2023

विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 181 के साथ पठित धारा 61, धारा 62, धारा 63 और धारा 86 के अधीन प्रदत्त शक्तियों और इस निमित्त समर्थकारी सभी अन्य शक्तियों का प्रयाग करके तथा पूर्व प्रकाशनों के पश्चात्, उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग एतद्वारा निम्नलिखित विनियमावली बनाते हैं, अर्थात् :-

1-संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ-

1.1 यह विनियमावली 'उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (टैरिफ निर्धारण की प्रक्रिया) विनियमावली, 2023' कही जायेगी।

1.2 यह विनियमावली राजकीय गज़ट में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी।

1.3 यह विनियमावली सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश राज्य में प्रवृत्त होगी।

2-परिभाषा :-

2.1 इस विनियमावली में जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो :

- (1) “अधिनियम” का तात्पर्य विद्युत अधिनियम, 2003 से है;
- (2) “आयोग” का तात्पर्य उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग से है;
- (3) “विद्यमान परियोजना” का तात्पर्य एक ऐसी परियोजना से है जिसने वाणिज्यिक परिचालन प्राप्त कर लिया है;
- (4) “अन्तःराज्यीय पारेषण प्रणाली” या “आईएनएसटीएस” का राज्य के संबंध में वही तात्पर्य होगा जो अधिनियम में परिभाषित है;
- (5) “चालू परियोजना” का तात्पर्य एक परियोजना से है जो कार्यान्वयन के अधीन है लेकिन वाणिज्यिक संचालन प्राप्त नहीं किया है;
- (6) “विनियमित टैरिफ तंत्र” या “आरटीएम” का तात्पर्य अधिनियम की धारा 62 के अधीन आयोग द्वारा निर्दिष्ट विनियमों के अनुसार आयोग द्वारा टैरिफ के निर्धारण से है;
- (7) “स्टेट ट्रांसमिशन यूटिलिटी” या “एसटीयू” का वही तात्पर्य होगा जो अधिनियम में परिभाषित है;
- (8) “एसटीयू पारेषण योजना” का तात्पर्य राज्य के लिए अद्यतन पंचवर्षीय रोलिंग अन्तःराज्यीय पारेषण प्रणाली योजना से है, जैसा कि एसटीयू द्वारा प्रतिवर्ष तैयार और जारी किया जाता है;
- (9) “टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली” या “टीबीसीबी” का तात्पर्य अधिनियम की धारा 63 के अधीन केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार बोली की पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से टैरिफ के निर्धारण से है;
- (10) “वर्ष” का तात्पर्य 01 अप्रैल से 31 मार्च तक के वित्तीय वर्ष से है।

2.2 उपर्युक्त को रक्षित करते हुए एवं जब तक संदर्भ के असंगत न हो या यदि विषय के संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, इस विनियमावली में प्रयुक्त शब्द और अभिव्यक्तियाँ जो इसमें परिभाषित नहीं हैं लेकिन अधिनियम या आयोग की किसी अन्य विनियमावली में परिभाषित हों, का वही अर्थ होगा जो उनके लिए अधिनियम या आयोग के किसी अन्य विनियमावली में दिया गया है। उसी प्रकार, इस विनियमावली में प्रयुक्त शब्द और अभिव्यक्तियाँ जो इसमें परिभाषित नहीं हैं लेकिन अधिनियम की धारा 63 के तहत केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देश में परिभाषित हो, का वही अर्थ होगा, जो उनके लिए जो इन दिशा-निर्देशों में दिया गया है।

2.3 किसी भी अधिनियमों, नियमों और विनियमों के संदर्भ में संशोधन या समेकन या पुनः अधिनियमन शामिल होगा।

2.4 इस विनियमावली के अंग्रेजी तथा हिन्दी संस्करण के बीच व्याख्या के अन्तर की स्थिति में अंग्रेजी व्याख्या प्रवृत्त होगी।

भाग-अ

**राज्य में वितरण अनुज्ञप्तिधारी के लिए
विद्युत क्रय अनुमोदन हेतु प्रक्रिया**

3-अधिनियम की धारा 62 के अधीन विद्युत क्रय :-

3.1 समस्त विद्यमान विद्युत उत्पादन परियोजनाएं जिनके लिए टैरिफ वर्तमान में अधिनियम की धारा 62 के अधीन विनियमित टैरिफ तंत्र (आरटीएम) के अनुसार निर्धारित किया जा रहा है, जिसमें वे भी शामिल हैं जिनके पीपीए आरटीएम के लिए आयोग द्वारा अनुमोदित किये गये हैं, धारा 62 के अन्तर्गत ही अभिरक्षित रहेंगे और तदनुसार ये परियोजनाएं आरटीएम ढांचे के अन्तर्गत शामिल की जाती रहेंगी और पीपीए की शेष अवधि या संयंत्र के जीवन, जो भी पहले हो, के लिए धारा 62 के अधीन उनकी टैरिफ निर्धारित की जायेगी।

3.2 राज्य के स्वामित्व और नियंत्रित विद्यमान विद्युत उत्पादन परियोजनाओं के विस्तार की अनुमति धारा 62 के तहत दी जायेगी और समय-समय पर संशोधित उ0प्र0वि0नि0आ0 (उत्पादन टैरिफ के नियम और शर्तें) विनियमावली में निर्दिष्ट मानदंडों के आधार पर उनके टैरिफ निर्धारित किये जायेगे।

प्रतिबन्ध यह है कि निजी विकासकर्ताओं द्वारा उत्पादन क्षमता के विस्तार के मामले में, वृद्धिशील उत्पादन क्षमता के लिए टैरिफ धारा 62 के अधीन आरटीएम ढांचे के अनुसार निर्धारित किया जायेगा। हलांकि, आरटीएम ढांचे के अधीन इस तरह का विस्तार राज्य में वितरण अनुज्ञप्तिधारी(यों) के साथ उनके विद्यमान पीपीए के तहत स्वीकृत विद्युत की मात्रा तक सीमित होगा।

3.3 राज्य में वितरण अनुज्ञप्तिधारी के साथ अनुमोदित पीपीए के अनुसार स्थापित सभी अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्रों से उत्पादित विद्युत।

3.4 पम्प हाइड्रो पावर प्लांट को सम्मिलित करते हुए सभी हाइड्रो पावर प्लांट के टैरिफ, जिसके लिए आयोग द्वारा पीपीए अनुमोदित किया गया है, धारा 62 के तहत आरटीएम ढांचे के अनुसार निर्धारित किया जायेगा।

4. अधिनियम की धारा 63 के अन्तर्गत अधीन विद्युत क्रय :-

विनियम 3 में सम्मिलित न होने वाले दीर्घ अवधि, मध्यम अवधि और एचपी-डीएम (हाई प्राइस डे अहेड मार्केट) के तहत सभी विद्युत क्रय के लिए टैरिफ, ऐसी क्षमता की आवश्यकता के लिए आयोग के पूर्व अनुमोदन के साथ अधिनियम की धारा 86(1)(बी) के अनुसरण में प्रतिस्पर्धात्मक बोली के माध्यम से चयनित किया जायेगा। अग्रेतर, टीबीसीबी दिशानिर्देशों से किसी भी विचलन के लिए आयोग के पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता होगी।

भाग-ब

पारेषण

5-एसटीयू पारेषण योजना:-

5.1 एसटीयू राज्य के लिए एक अद्यतन पंचवर्षीय पारेषण प्रणाली योजना (विशिष्ट पारेषण परियोजनाओं की पहचान करना जिन्हें अन्य के साथ लिया जाना आवश्यक है (अ) संक्षिप्त कार्यक्षेत्र; (ब) अनुमानित लागत; (स) अनुमानित सीओडी/कार्यान्वयन समयसीमा) भारतीय विद्युत ग्रिड संहिता और केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के अन्य दिशानिर्देशों/विनियमों के साथ पठित राज्य ग्रिड संहिता के अनुसार प्रति वर्ष 28 फरवरी तक रोलिंग आधार पर (या राज्य ग्रिड संहिता में अन्तर्निहित) आयोग के अनुमोदन के लिए तैयार करेगा।

5.2 सभी अन्तःराज्यीय पारेषण परियोजनायें एसटीयू पारेषण योजना के अनुरूप होंगी। किसी भी अन्तःराज्यीय पारेषण परियोजना के कार्यान्वयन पर विचार नहीं किया जायेगा, जब तक कि परियोजना एसटीयू पारेषण योजना का भाग न हो और आयोग द्वारा तदनुसार अनुमोदित न किया गया हो।

6-अधिनियम की धारा 63 के अधीन आईएनएसटीएस परियोजनाओं के लिए टैरिफ निर्धारण:-

6.1 220 केवी और उससे अधिक वोल्टेज स्तर की सभी नई ग्रीनफील्ड अन्तःराज्यीय पारेषण परियोजनायें, एसटीयू पारेषण योजना का हिस्सा होने के नाते, अधिनियम की धारा-63 के अधीन जारी दिशानिर्देशों के अनुसार टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली (टीबीसीबी) के माध्यम से कार्यान्वयित की जायेंगी और दिशानिर्देशों से किसी भी विचलन की दशा में आयोग द्वारा पूर्व में अनुमोदित होना चाहिए। ऐसी अन्तःराज्यीय पारेषण परियोजनाओं की टैरिफ अधिनियम की धारा 63 के अधीन चयनित की जायेगी।

प्रतिबन्ध यह है कि एसटीयू पारेषण योजना का हिस्सा होने के नाते निम्नलिखित नई ग्रीनफील्ड अन्तःराज्यीय पारेषण परियोजनाओं को आयोग के पूर्व अनुमोदन के अधीन आरटीएम ढांचे (अधिनियम की धारा 62 के तहत) के अन्तर्गत शामिल किया जायेगा:

(अ) रणनीतिक महत्व की अन्तःराज्यीय पारेषण परियोजनायें या अत्यावश्यक स्थिति को पूरा करने के लिए आवश्यक कार्य, जहां इस तरह के महत्व या अत्यावश्यकता के प्रस्ताव को राज्य सरकार की संस्तुति द्वारा समर्थन किया जाता है;

(ब) डिपाजिट वर्क, जिनकी निधियों का लेखा उपभोक्ता अंशदान के तहत किया जाता है;

(स) छोटी योजनायें जैसे कि लीलो लाइनें, चाहे किसी शहर के बाईपास या अन्यथा के उद्देश्य से हों, और जिसकी लागत 100 करोड़ रुपये से अधिक न हो। हालांकि, परियोजना के पूरा होने के बाद, अगर यह पाया जाता है कि खर्च की गई पूंजीगत लागत 100 करोड़ रुपये की अधिकतम सीमा से अधिक हो गई है, तो ऐसी अधिक खर्च की गयी राशि को विनियमित टैरिफ के अधीन आरोपित नहीं किया जायेगा और पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अपने स्वयं के संचय/लागत के माध्यम से वहन किया जायेगा।

7—अधिनियम की धारा 62 के अधीन आईएनएसटीएस परियोजनाओं के लिए टैरिफ निर्धारण:—

7.1 एसटीयू पारेषण योजना का हिस्सा होने के नाते, विनियम 6.1 के अंतर्गत शामिल नहीं की गई अन्य सभी अन्तःराज्यीय पारेषण परियोजनाओं के लिए टैरिफ, अधिनियम की धारा 62 के अधीन आरटीएम ढांचे के अनुसार निर्धारित किया जायेगा।

7.2 एसटीयू पारेषण योजना का हिस्सा होने के नाते अन्तःराज्यीय पारेषण सबस्टेशन और/या लाइन पर संवर्द्धन/सुदृढीकरण कार्यों (ओ एंड एम कार्यों को छोड़कर) का कार्यान्वयन, संबंधित विकासकर्ता द्वारा उ०प्र०वि०नि०आ० (बहुवर्षीय वितरण और पारेषण टैरिफ) विनियमावली 2019, समय-समय पर संशोधित, के साथ पठित अधिनियम की धारा 62 के तहत प्रावधानों के अनुसार किया जायेगा, जिसके लिए एसटीयू मामले-दर-मामले के आधार पर आयोग का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करेगा।

भाग-स

वितरण

8—उपभोक्ताओं का खुदरा टैरिफ विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 62 के साथ-साथ उ०प्र०वि०नि०आ० (बहुवर्षीय वितरण और पारेषण टैरिफ) विनियमावली 2019, समय-समय पर संशोधित, के अनुसार निर्धारित किया जायेगा।

भाग-द

विविध

9—शिथिलीकरण की शक्ति :—

आयोग प्रभावित हो सकने वाले पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात् तथा लिखित में कारणों को अंकित कर सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा आने स्वविवेक पर अथवा इसके समक्ष प्रभावित व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र पर इस विनियमावली के किसी भी प्राविधान को शिथिल कर सकता है।

10—कठिनाई निवारण की शक्ति :—

इस विनियमावली को लागू करने पर यदि कोई कठिनाई आती है, आयोग अपने स्वविवेक पर अथवा किसी भी प्रभावित पक्ष द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र पर ऐसे निर्देश निर्गत कर सकता है जो इस विनियमावली के उद्देश्य के विस्तार हेतु आवश्यक समझे जायें।

आयोग के आदेशानुसार,
डा० संजय कुमार सिंह,
सचिव

UTTAR PRADESH ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION LUCKNOW

No. UPERC/Secy./Regulation/746

Lucknow: dated : February 28, 2023

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred under Section 181 read with Section 61, Section 62, Section 63 and Section 86 of the Electricity Act 2003 and all other powers enabling it in this behalf, and after previous publication, the Uttar Pradesh Electricity Regulatory Commission hereby makes the following regulations, namely:

1. Short Title and Commencement :—

1.1 These regulations may be called the Uttar Pradesh Electricity Regulatory Commission (Modalities of Tariff Determination) Regulations, 2023.

1.2 These regulations shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

1.3 These regulations shall extend to the whole of the State of Uttar Pradesh.

2. Definitions :—

2.1 In these regulations, unless the context otherwise requires:

- (1) “Act” means the Electricity Act, 2003;
- (2) “Commission” means the Uttar Pradesh Electricity Regulatory Commission;
- (3) “Existing Project” means a project which has achieved commercial operation;
- (4) “Intra-State Transmission System” or “InSTS” in respect of the State shall have the same meaning as defined in the Act;
- (5) “Ongoing Project” means a project which has been under implementation but has not achieved commercial operation;
- (6) “Regulated Tariff Mechanism” or “RTM” means determination of tariff by the Commission in accordance with the regulations specified by the Commission under Section 62 of the Act;
- (7) “State Transmission Utility” or “STU” shall have the same meaning as defined in the Act;
- (8) “STU Transmission Plan” means an updated five-year rolling Intra-State Transmission System Plan for the State as prepared and issued every year by STU;
- (9) “Tariff Based Competitive Bidding” or “TBCB” means determination of tariff through transparent process of bidding in accordance with the guidelines issued by the Central Government under Section 63 of the Act;
- (10) “Year” means a financial year from 1st April to 31st March.

2.2 Save as aforesaid and unless repugnant to the context or if the subject matter otherwise requires, words and expressions used in these regulations and not defined here, but defined in the Act or any other regulations of this Commission shall have the meaning assigned to them under the Act, or any other regulations of this Commission. Similarly, words and expressions used in these regulations and not defined here, but defined in the guidelines issued by the Central Government under Section 63 of the Act shall have the meaning as assigned to these in the guidelines.

2.3 Reference to any Acts, Rules and Regulations shall include amendments or consolidation or re-enactment thereof.

PART-A

MODALITY FOR POWER PURCHASE APPROVAL FOR THE DISTRIBUTION LICENSEE IN THE STATE

3. Power Procurement under Section 62 of the Act :—

3.1 All existing power generating projects for which tariff is currently being determined in accordance with Regulated Tariff Mechanism (RTM) under Section 62 of the Act, including those whose PPA(s) have been approved by the Commission for RTM, shall be grandfathered and accordingly these projects will continue to be covered under RTM framework and their tariffs will be determined under Section 62 for the remainder of the PPA period or life of the plant, whichever is earlier.

3.2 Expansion of existing state owned and controlled power generating projects will be allowed under Section 62 and their tariffs shall be determined based on norms specified in the UPERC (Terms and Conditions of Generation Tariff) Regulations, as amended from time to time.

Provided that in case of expansion of generating capacity by private developers, the tariffs for the incremental generating capacity would be determined in accordance with RTM framework under Section 62. However, such expansion under RTM framework would be restricted up to the quantum of power approved under their existing PPA with the distribution licensee(s) in the state.

3.3 Power produced from all Waste-to-Energy plants set up as per approved PPA with the distribution licensee in the State.

3.4 Tariff of all Hydro Power Plants including Pump Hydro Power Plants, for which PPA has been approved by the Commission, shall be determined in accordance with RTM framework under Section 62.

4. Power Procurement under Section 63 of the Act :-

Tariff for all power procurement under long term, medium term not covered in Regulation 3 and HP-DAM (High Price Day Ahead Market) shall be discovered through competitive bidding route with prior approval of the Commission for the requirement of such capacity to be bid in pursuance to Section 86 (1)(b) of the Act. Further, any deviation from TBCB guidelines shall require prior approval of the Commission.

PART-B TRANSMISSION

5. STU Transmission Plan :-

5.1 The STU shall prepare an updated five-year Transmission System Plan for the State (identifying specific transmission projects which are required to be taken up along with others (a) Brief Scope of Work; (b) Estimated Cost; (c) Estimated COD/implementation timelines) for approval of the Commission by 28th February on rolling basis every year (or as stipulated in the State Grid Code) in accordance with the State Grid Code read with Indian Electricity Grid Code and other guidelines/ regulations of Central Electricity Authority.

5.2 All intra-State transmission projects shall be consistent with the STU Transmission Plan. **No intra-State transmission project shall be considered for implementation, unless the project is a part of the STU Transmission Plan and has been duly approved by the Commission.**

6. Tariff Determination for InSTS Projects under Section 63 of the Act :-

6.1 All new greenfield intra-State transmission projects of 220 kV & above voltage level, being part of the STU Transmission Plan, shall be implemented through Tariff Based Competitive Bidding (TBCB) in accordance with the guidelines issued under Section 63 of the Act and any deviation from the guidelines should have prior approval of the Commission. The tariff of such intra-State transmission projects shall be discovered under Section 63 of the Act.

Provided that following new greenfield intra-State transmission projects, being part of the STU Transmission Plan, shall be covered under RTM framework (under Section 62 of the Act) subject to prior approval of the Commission:

(a) Intra-State transmission projects of strategic importance or works required for catering to an urgent situation, where proposal of such importance or urgency is supported by the recommendation of the State Government;

- (b) Deposit works, whose funds are accounted for under consumer contribution;
- (c) Small schemes such as LILO lines, whether for the purpose of a city bypass or otherwise, and entailing a cost not exceeding Rs. 100 Crores. However, after completion of project, if it is found that the capital cost incurred has exceeded the ceiling limit of Rs 100 Crores, then such excess amount shall not be passed under Regulated Tariff and shall be borne by the transmission licensee through its own reserve/cost.

7. Tariff Determination for InSTS Projects under Section 62 of the Act :-

- 7.1 Tariff for all other intra-State transmission projects not covered under Regulation 6.1, being part of the STU Transmission Plan, shall be determined in accordance with RTM framework under Section 62 of the Act.
- 7.2 Implementation of augmentation/ strengthening works (excluding O&M works) at the intra-State transmission substation and/or line, being part of the STU Transmission Plan, shall be carried out by the respective developer in accordance with the provisions under Section 62 of the Act read with UPERC (Multi Year Tariff for Distribution and Transmission) Regulations 2019, as amended from time to time, for which the STU shall obtain prior approval of the Commission on case-to-case basis.

PART-C DISTRIBUTION

8. Retail Tariff of the consumers shall be determined in accordance with Section 62 of the Electricity Act 2003 along with UPERC (Multi Year Tariff for Distribution and Transmission) Regulations 2019, as amended from time to time.

PART-D MISCELLANEOUS

9. Power to Relax :-

The Commission may by general or special order, for reasons to be recorded in writing, and after giving an opportunity of hearing to the parties likely to be affected, may relax any of the provisions of these regulations on its own motion or on an application made before it by the affected party.

10. Power to Remove Difficulties :-

If any difficulty arises in giving effect to these regulations, the Commission may on its own motion or on an application filed by any affected party, issue such practice directions as may be considered necessary in furtherance of the objective of these regulations.

By the Order of the Commission,
DR. SANJAY KUMAR SINGH,
Secretary,
U. P. Electricity Regulatory Commission.